महाराष्ट्र राज्य

बनाम

हंस राज डेपर आदि

25 फरवरी, 1977

(वाई. वी. चंद्रचूड़, पी. के. गोस्वामी और पी. एन. सिंहल, जे. जे.)

महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तु (मूल्यों का प्रदर्शन और अंकन) आदेश, 1966, खंड 3 (ए) और (4) -आशय का अर्थ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का अधिनियम 10) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तु (मूल्यों का प्रदर्शन और अंकन) आदेश, 1966 का खंड 3 (ए) प्रदान करता है कि "प्रत्येक विक्रेता अनुसूची 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में कीमतों की एक सूची प्रदर्शित करेगा", अनुसूची 1 में क्रमशः 15 और 16 "वनस्पति डिब्बाबंद" और "वनस्पति मुक्त" वस्तुओं के तहत सूचियां दी गई हैं। आदेश के खंड (4) में प्रावधान है कि कोई भी व्यापारी (ए) प्रदर्शित मूल्य से अधिक कीमत पर किसी भी वस्तु को बेचेगा या सहमत नहीं होगा या बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा या (बी) किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शित या चिह्नित मूल्य पर ऐसी वस्तुओं को बेचने या बेचने से इनकार करेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 में धारा 3 के तहत दिए गए आदेश के उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान है।

चार उत्तरदाता, बॉम्बे में दुकानदार-कुछ किराने की दुकानें चलाते हैं, जबकि कुछ केवल विभिन्न प्रकार के तेलों का सौदा करते हैं-उन पर वनस्पति की कीमतों को प्रदर्शित करने में विफलता के अपराध के लिए आरोप लगाया गया था, जिन्हें वे अपनी दुकानों में डिब्बाबंद और ढीले रूप में बेच रहे थे। आरोप के प्रति उत्तरदाताओं का बचाव यह है कि वे वनस्पति नहीं, बल्कि हाइड्रोजनीकृत तेल या वनस्पति घी या वनस्पति तेल बेच रहे थे। विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थियों को बरी कर दिया और कहा कि आरोप अस्थिर था क्योंकि (1) भले ही 'वनस्पति' शब्द ने स्थानीय अर्थ प्राप्त कर लिया हो, यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश में हाइड्रोजनीकृत तेलों को शामिल करने के लिए 'वनस्पति' शब्द का उपयोग किया गया था। (2) चूंकि हाइड्रोजनीकृत तेलों को अनुसूची 1 में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उत्तरदाताओं से यह जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वे हाइड्रोजनीकृत तेल की कीमतों का खुलासा करने के लिए बाध्य थे। राज्यों की अपील को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने एक अलग तर्क पर अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि आदेश 1966 के खंड (3) का गैर-अनुपालन, उल्लंघन के रूप में दंडनीय अपराध नहीं हो सकता है जब तक कि खंड 4 का उल्लंघन न हो, क्योंकि विधानमंडल का इरादा जो हमेशा कानून के उल्लंघन और इसका पालन करने में विफलता या गैर-अनुपालन के बीच अंतर करता है, खंड 4 के उल्लंघन को दंडित करना था, न कि खंड 3 सरलीकरण के।

राज्य की अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

(1) महाराष्ट्र अनुसूचित (मूल्यों का प्रदर्शन और अंकन) आदेश, 1966 का खंड 3 और 4 अलग-अलग मामलों से संबंधित है क्योंकि जहां-जैसा कि खंड 3 अनुसूची 1 खंड 4 में निर्दिष्ट वस्तुओं की कीमतों को प्रदर्शित करने के लिए एक व्यापारी पर दायित्व

लगाता है, वह किसी वस्तु को प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने या प्रदर्शित मूल्य पर बेचने से इनकार करने से मना करता है। खंड 3 (ए) का उल्लंघन केवल इस तथ्य के कारण पूर्ण और पूर्ण है कि विक्रेता अनुसूची 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं की कीमतों को प्रदर्शित करने में विफल रहा है। यह उल्लंघन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसने निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत कहाँ ली है या उसने प्रदर्शित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से इनकार कर दिया है। दूसरे शब्दों में, एक व्यापारी को जो पहला कदम उठाना है, वह अनुसूची 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं की कीमतों को प्रदर्शित करना है; यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह खंड 3 (ए) के उल्लंघन का दोषी है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 (1) के तहत दंडनीय है। विक्रेता को जो अतिरिक्त दायित्व निभाना होता है, वह यह है कि वह प्रदर्शित कीमतों पर वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार और इच्छुक हो। ऐसा करने में विफलता एक अलग और विशिष्ट उल्लंघन है जो धारा 7 (1) के अनुप्रयोग को भी आकर्षित करता है। यह विचार कि आदेश 1966 के खंड 3 और 4 इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि विधानमंडल का इरादा पूर्व के उल्लंघन को दंडित करने का नहीं था, जब तक कि इस तरह के उल्लंघन के साथ बाद के प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया था, सही नहीं है। इस तरह से दोनों खंडों का विवाह पूरी तरह से अनुचित है। [81 ई-एच 82-ए]

(2) तत्काल मामले में बरी किए जाने के आदेशों की पुष्टि इस आधार पर की जानी चाहिए कि सबूतों की कमी से पता चलता है कि प्रतिवादी वनस्पति के व्यापारी हैं और उन्होंने अपनी दुकानों में बिक्री के लिए वनस्पति रखी थी। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए कि जो बेचा जा रहा था वह वनस्पति नहीं था और टिन में अनुसूची 1 की मद 15 और 16 के अर्थ के भीतर वनस्पति नहीं थी, अभियोजन पक्ष को यह दिखाने के लिए साक्ष्य देना चाहिए था कि टिन में वास्तव में वनस्पति थी। पंचों की जांच किए बिना और कथित रूप से बेचे जाने वाले "वनस्पति" का कोई नमूना लिए बिना, जिन

उप-निरीक्षक ने केवल छापेमारी करने में राशन निरीक्षक की सहायता की थी, बिना उन वस्तुओं की किसी सूची के, जिनकी कीमतें प्रदर्शित नहीं की गई थीं, केवल अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा आरोप स्थापित नहीं कर सकते हैं जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 (1) (ए) (iii) में दिए गए प्रावधान के अनुसार सात साल तक की अवधि और आम तौर पर तीन महीने से कम की सजा शामिल है। [82 एफ-एच, 84 सी]

(3) न तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और न ही महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तु (मूल्यों का प्रदर्शन और अंकन) आदेश 1966 "वनस्पति" शब्द को परिभाषित करता है और यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि "वनस्पति" को बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम और खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1965 में हाइड्रोजनीकृत तेल को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है क्योंकि इन तीन अधिनियमों के उद्देश्य काफी अलग हैं। अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि "वनस्पति" अभिव्यक्ति का सही अर्थ और अर्थ क्या है और उस अभिव्यक्ति के दायरे में किस प्रकार के लेखों को समझा जाता है। [83 बी-एच]

(4) आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के अनुसार, जो निष्पक्षता को दर्शाता है, एक व्यापारी को उचित निश्चितता के साथ पता होना चाहिए और उसे इस बारे में उचित चेतावनी होनी चाहिए कि उसका दायित्व क्या है, और उसकी ओर से कमीशन या चूक का कौन सा कार्य एक आपराधिक अपराध होगा। राज्य सरकार को हाइड्रोजनीकृत तेल को आइटम 15 और 16 में शामिल करके अपनी मंशा स्पष्ट और स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी चाहिए थी, जो "वनस्पति" को संदर्भित करते हैं। यदि ऐसा किया जाता, तो इस मामले में उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की दुर्दशा को समुदाय के लाभ के साथ आसानी से टाला जा सकता था। [84 ए-बी]

बिहार राज्य बनाम भागीरथ शर्मा, (1973) 3 एस. सी. आर. 937, संदर्भित;

[न्यायालय ने आशा व्यक्त की कि महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तु (मूल्यों का प्रदर्शन और अंकन) आदेश, 1966 की अनुसूची 1 मद 15 और 16 में कमी को शीघ्रता से ठीक किया जाएगा।]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 156-159/1973

(आपराधिक अपील संख्या 1475/69 और 70 के 370-372 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित 3-3-1971 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील)।

सभी अपीलों में अपीलार्थी के लिए एम. एन. फड़के और एम. एन. श्रॉफ।

आपराधिक अपील संख्या 158/73 में प्रतिवादी के लिए वाई. एस. चिताले, एम. मुद्गल और रामेश्वर नाथ।

रामेश्वर नाथ, आपराधिक अपील संख्या 159/73 में प्रतिवादी के लिए)।

न्यायालय का निर्णय चंद्रचूड़, जे द्वारा दिया गया था :-

इन चार अभियोजनों में से चार अपीलें उत्पन्न होती हैं जिन्हें विद्वान प्रेसीडेंस मजिस्ट्रेट, 25 वीं अदालत, मझगांव, बॉम्बे द्वारा एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया गया था। अभियोजन की ओर ले जाने वाले तथ्य चारों मामलों में सभी मामलों में समान नहीं हैं, लेकिन विचाराधीन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि मामलों की सुनवाई और निपटान इस आधार पर किया गया था कि तथ्यों में भिन्नता से परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन अपीलों में चार उत्तरदाता बॉम्बे में दुकानदार हैं-कुछ किराने की दुकानें चलाते हैं जबकि कुछ केवल विभिन्न प्रकार के तेलों का सौदा करते हैं। उत्तरदाताओं के

खिलाफ आरोप यह है कि वे 'वनस्पति' की कीमतों को प्रदर्शित करने में विफल रहे जिन्हें वे अपनी दुकानों में डिब्बाबंद और खुले रूप में बेच रहे थे।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 10 केंद्र सरकार को आदेश द्वारा किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण या व्यापार और वाणिज्य को उप-धारा (1) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए विनियमित करने या प्रतिबंधित करने का प्रावधान करने का अधिकार देती है। धारा 3 की उप-धारा (2) विभिन्न मामलों को निर्दिष्ट करती है जिनके संबंध में केंद्र सरकार उप-धारा (1) द्वारा अनुध्यात आदेश पारित कर सकती है। धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 में निहित प्रावधान के अनुसरण में राज्य सरकारों को सौंप दी गई थी। धारा 7 में धारा 3 के तहत दिए गए आदेश के उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र अनुसूचित अनुच्छेद (मूल्यों का प्रदर्शन और अंकन) आदेश, 1966 जारी किया। उस आदेश के खंड 3 (ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक विक्रेता, अनुसूची 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में, उस अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में कीमतों की एक सूची प्रदर्शित करेगा। हम अनुसूची की मद 15 और 16 से संबंधित हैं जिसमें लिखा हैः "15. वनस्पति, टिन " और " 16. वनस्पति, लूज़।"

मोटे तौर पर, आरोप के प्रति उत्तरदाताओं का बचाव यह है कि वे हाइड्रोजनीकृत तेल या वनस्पति घी या वनस्पति तेल बेच रहे थे न कि 'वनस्पति'।

विद्वान मजिस्ट्रेट ने चारों मामलों में प्रतिवादियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि भले ही 'वनस्पति' शब्द का स्थानीय अर्थ हो गया हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश में हाइड्रोजनीकृत तेलों को शामिल करने के लिए 'वनस्पति' शब्द

का उपयोग किया गया था। चूंकि विद्वत मजिस्ट्रेट के अनुसार, उत्तरदाताओं से यह जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वे हाइड्रोजनीकृत तेलों की कीमतों का खुलासा करने के लिए भी बाध्य थे और चूंकि हाइड्रोजनीकृत तेलों को अनुसूची 1 में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए शुल्क अस्थिर था।

बरी किए जाने के आदेशों के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई की गई और उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 3 मार्च, 1971 के एक सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया गया। यह देखते हुए कि राज्य सरकार के इस तर्क में काफी बल था कि 'वनस्पति' में हाइड्रोजनीकृत तेल भी शामिल होंगे, विद्वान न्यायाधीश ने महसूस किया कि उस प्रश्न में जाना अनावश्यक था क्योंकि अभियोजन पक्ष किसी अन्य कारण से विचारणीय नहीं था। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, इसका कारण यह था कि विधायी मसौदा तैयार करने वाले हमेशा कानून के 'उल्लंघन' और 'अनुपालन करने में विफलता या गैर-अनुपालन' के बीच अंतर करते थे। विद्वान न्यायाधीश का कहना है कि यदि न्यायालय को यह तय करने के लिए कहा जाता है कि क्या कोई विशेष उल्लंघन एक अपराध है, तो यह जांच करने के लिए बाध्य था कि क्या केवल गैर-अनुपालन को दंडित करने का भी इरादा था। उस सिद्धांत द्वारा निर्देशित, विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मूल्यों को प्रदर्शित करने का कर्तव्य "निषेध का एक सहायक मामला था जिसमें खंड 4 शामिल है जो एक व्यापारी को प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने या बेचने से इनकार करने या बिक्री से ऐसी वस्तुओं को प्रदर्शित या चिह्नित मूल्य पर रखने से रोकता है। इस प्रकार आदेश का निर्वाह खंड 4 में निहित माना गया था और तदनुसार, निर्णय आगे बढ़ता है; "केवल खंड 3 का गैर-अनुपालन उल्लंघन के रूप में दंडनीय अपराध नहीं हो सकता है जब तक कि खंड 4 का उल्लंघन न हो।" चूँकि इरादा खंड 4 के उल्लंघन को दंडित करने के लिए कहा गया था न कि खंड 3 के सरलीकरण के लिए, विद्वान

न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष विचारणीय नहीं था और अभियुक्त बरी होने के हकदार थे। विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं।

व्यापक लोक हित में 1966 के आदेश के खंड 3 और 4 के सही अर्थ और इरादे के बारे में गलतफहमी को दूर करना आवश्यक है। इसलिए हम पहले उच्च न्यायालय के इस तर्क पर विचार करेंगे कि खंड 4 के उल्लंघन के बिना खंड 3 का केवल उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अर्थ के भीतर उल्लंघन नहीं है और इसलिए इसे दंडित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, 1966 के आदेश का खंड 3 (ए) प्रत्येक विक्रेता पर अनुसूची 1 में निर्दिष्ट वस्तु की कीमतों की सूची प्रदर्शित करने का दायित्व लगाता है। आदेश के खंड 4 में प्रावधान है कि कोई भी व्यापारी (ए) प्रदर्शित मूल्य से अधिक कीमत पर किसी भी वस्तु को बेचेगा या सहमत नहीं होगा या बिक्री की पेशकश नहीं करेगा या (बी) किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शित या चिह्नित मूल्य पर ऐसी वस्तुओं को बेचने या बिक्री से रोकने से इनकार करेगा। हम खुद को यह समझने में पूरी तरह से असमर्थ पाते हैं कि वह खंड 3 (ए) का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है जब तक कि खंड 4 का भी उल्लंघन न हो। दोनों खंड अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं क्योंकि खंड 3 एक व्यापारी पर अनुसूची 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं की कीमतों को प्रदर्शित करने का दायित्व लगाता है, खंड 4 उसे प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने या प्रदर्शित मूल्य पर इसे बेचने से इनकार करने से रोकता है। खंड 3 (ए) का उल्लंघन केवल इस तथ्य के कारण पूर्ण और पूर्ण है कि विक्रेता अनुसूची 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं की कीमतों को प्रदर्शित करने में विफल रहा है। यह उल्लंघन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि क्या उसने निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया है या उसने प्रदर्शित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से इनकार कर दिया है। दूसरे शब्दों में, एक व्यापारी को जो पहला कदम उठाना है, वह अनुसूची 1 में

निर्दिष्ट वस्तुओं की कीमतों को प्रदर्शित करना है; यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह खंड 3 (ए) के उल्लंघन का दोषी है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 (1) के तहत दंडनीय है। विक्रेता को जिस अतिरिक्त दायित्व का निर्वहन करना है, वह यह है कि वह प्रदर्शित कीमतों पर वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार और इच्छुक हो; ऐसा करने में विफलता एक अलग और विशिष्ट उल्लंघन है जो धारा 7 (1) के आवेदन को भी आकर्षित करता है। हम इस विचार को स्वीकार करना असंभव पाते हैं कि 1966 के आदेश के खंड 3 और 4 इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि विधायिका का इरादा पूर्व के उल्लंघन को दंडित करने का नहीं था जब तक कि इस तरह के उल्लंघन के साथ बाद के प्रावधान का उल्लंघन न हो। इस तरह से दोनों खंडों का विवाह पूरी तरह से अनुचित है। जिस आधार पर उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को बरी किया है, वह इसलिए असमर्थनीय है और हम उस ओर के तर्क को अस्थिर बताते हुए अस्वीकार करते हैं। यदि हम संतुष्ट होते कि उत्तरदाता 'वनस्पति' बेच रहे थे, डिब्बाबंद या खुले, तो हमें बरी करने के आदेश को दरकिनार करने और उत्तरदाताओं को दोषी ठहराने में कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि कीमतों का प्रदर्शन न करना स्वीकार किया जाता है।

इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह मानने के लिए सबूत हैं कि उत्तरदाता 'वनस्पति' में काम कर रहे थे। इस प्रश्न पर साक्ष्य दयनीय रूप से अपर्याप्त है और हमें यह देखते हुए खेद है कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप स्थापित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया था। जिन वस्तुओं की कीमतें प्रदर्शित नहीं की गई थीं, उनका ठीक से आविष्कार नहीं किया गया था, जिससे यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि उन वस्तुओं में कोई विशेष विवरण था। पंचनामों को वस्तुओं से बनाया जाता था, लेकिन एक मामले को छोड़कर, जहां पंचनामों को सहमति से प्रदर्शित किया गया था, पंचों की जांच इस परिणाम के साथ नहीं की गई थी कि पंचनाम अप्रमाणित रहे और इसलिए अप्रकाशित रहे। किसी भी मामले में बिक्री के लिए प्रदर्शित वस्तुओं

का नमूना भी नहीं लिया गया था। यदि ऐसा किया जाता, तो रासायनिक रूप से नमूने का विश्लेषण करके माल की प्रकृति, गुणवत्ता और घटकों को आसानी से साबित किया जा सकता था। तब कोई भी आसानी से कह सकता था कि जो बेचा जा रहा था वह 'वनस्पति' था। जो करना आसान और आवश्यक था, उसे करने के बजाय, अभियोजन पक्ष ने अपने सादे कर्तव्य के विकल्प के रूप में, एक राशन निरीक्षक और पुलिस के एक उप निरीक्षक की अस्पष्ट यादों की पेशकश की कि उत्तरदाताओं द्वारा अपनी दुकानों में क्या बेचा जा रहा था।

यह स्पष्ट करने के लिए कि अभियोजन पक्ष ने अपने कार्य को कितनी लापरवाही से पूरा किया, हम 1973 की अपील संख्या 156 के तथ्यों को लेंगे जिसमें प्रतिवादी एक हंसराज डेपर है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा बनाए गए आरोप में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी 'वनस्पति घी' की मूल्य सूची प्रदर्शित करने में विफल रहा था। शुल्क किसी भी प्रकार के घी के संबंध में नहीं होना चाहिए था, बल्कि 'वनस्पति' के संबंध में होना चाहिए था जो अनुसूची 1 में उल्लिखित वस्तु है। राशन निरीक्षक, के. एन. जोशी (पीडब्लू. 1) ने अपने साक्ष्य में कहा कि प्रतिवादी ने 'वनस्पति घी' की कीमत का प्रदर्शन नहीं किया था जो फिर से बात से परे है। कुछ भी नहीं, यहां तक कि वनस्पति के रूप में कथित वस्तुओं का एक नमूना भी दुकान से नहीं लिया गया था और गवाह ने स्वीकार किया कि उसे याद नहीं था कि दुकान में किस प्रकार की वस्तुएं बेची गई थीं और वनस्पति घी के कितने डिब्बे पाए गए थे। दूसरे गवाह, सब इंस्पेक्टर कुर्दुर (पीडब्लू 2) का कहना है कि प्रतिवादी वनस्पति के साथ-साथ तेल भी बेच रहा था और उसकी दुकान में "रवि वनस्पति के 3 किलो टिन, प्रभात वनस्पति के 2 किलो टिन और मलाली वनस्पति का एक ढीला टिन" था। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए कि जो बेचा जा रहा था वह वनस्पति नहीं था और अनुसूची 1 की मद 15 और 16 के अर्थ के भीतर टिन में वनस्पति नहीं थी, अभियोजन पक्ष को यह दिखाने

के लिए साक्ष्य देना चाहिए था कि टिन में वास्तव में वनस्पति थी जिस अर्थ में उस अभिव्यक्ति का उपयोग अनुसूचित में किया गया है। छापेमारी को प्रभावी बनाने में केवल राशन निरीक्षक की सहायता करने वाले उप निरीक्षक का अप्रत्यक्ष आदेश उस आरोप को स्थापित नहीं कर सकता है जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 (1) (ए) (ii) में प्रदान की गई सात साल की लंबी अवधि और आम तौर पर तीन महीने से कम की सजा शामिल है।

अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया कि 'वनस्पति' अभिव्यक्ति का सही अर्थ और अर्थ क्या है और उस अभिव्यक्ति के दायरे में किस तरह की वस्तुओं या वस्तुओं को समझा जाता है। गवाहों ने अपने साक्ष्य में यह भी नहीं कहा कि इस शब्द ने एक लोकप्रिय अर्थ प्राप्त कर लिया था और एक निश्चित अर्थ में स्थानीय रूप से समझा गया था। न तो 1955 के अधिनियम और न ही 1966 के आदेश में 'वनस्पति' अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है और यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम और खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1965 में हाइड्रोजनीकृत तेल को शामिल करने के लिए 'वनस्पति' को परिभाषित किया गया है। बिक्री कर अधिनियम का उद्देश्य खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम और उसके तहत नियमों की यथासंभव बड़ी संख्या में वस्तुओं को कर के दायरे में लाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुदाय का स्वास्थ्य मिलावटी या नकली खाद्य पदार्थों से खतरे में न पड़े, जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसके साथ हम तत्काल मामले में चिंतित हैं, समुदाय को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह अंतिम अधिनियम "आम जनता के हित में, कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण के लिए" प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। उप निरीक्षक कुर्दुर इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं हैं और हम बिना किसी और के, इन मामलों में से एक में उनके द्वारा

किए गए हठधर्मी दावे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि वनस्पति और हाइड्रोजनीकृत तेल का "एक ही अर्थ है"। हाइड्रोजनीकरण एक विशेष प्रक्रिया है और इसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (1951 संस्करण, खंड 11, पृष्ठ 978) में "हाइड्रोजन के साथ एक पदार्थ का उपचार" के रूप में वर्णित किया गया है ताकि यह सीधे उपचारित पदार्थ के साथ जुड़ जाए। हालाँकि, इस शब्द ने एक अधिक तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थ विकसित किया है। अब इसका उपयोग आम तौर पर हाइड्रोजन के साथ एक "असंतृप्त" कार्बनिक यौगिक के उपचार के लिए किया जाता है, ताकि इसे एक "संतृप्त" यौगिक में सीधे जोड़कर परिवर्तित किया जा सके। गवाह, क्षमा करने योग्य रूप से, इस वैज्ञानिक पक्ष से अनजान लगता है और अज्ञानता जितनी अधिक होगी, हठधर्मिता उतनी ही अधिक होगी। यदि गवाह सही था, तो यह समझना मुश्किल है कि क्यों 'मूंगफली का तेल, केसर का तेल, तिल का तेल और सरसों के बीज का तेल' और 'नारियल के तेल' को अनुसूची 1 में आइटम 5 और 6 में एक अलग और विशिष्ट स्थान मिलता है। शायद गवाह ने जो अनुमान लगाया, विज्ञान शायद धीरे-धीरे सच हो सकता है, लेकिन इसे दिखाया जाना चाहिए, अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए।

बिहार राज्य बनाम भागीरथ शर्मा (') में एक सवाल उठा कि क्या मोटर कार के टायरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा 1967 में जारी किए गए' समान आदेश 'में उपयोग किए गए' ऑटोमोबाइल के घटक भागों और सहायक उपकरणों 'के अर्थ के भीतर शामिल किया गया था। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह पर्याप्त नहीं था कि व्यापक दृष्टिकोण से मोटर कारों के टायर और ट्यूबों को विशेष अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया जा सकता है। विशेष अनुसूची में विभिन्न मदों पर विचार करने और उनकी तुलना करने के बाद इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मोटर कार के टायरों को अभिव्यक्ति के भीतर नहीं समझा गया था। अदालत ने उस मामले में जो कहा, उस पर ध्यान आकर्षित करना

हमारे उद्देश्य के लिए उचित है, अर्थात्, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के अनुसार, जो निष्पक्षता को दर्शाता है, एक व्यापारी को उचित निश्चितता के साथ पता होना चाहिए और उसे इस बारे में उचित चेतावनी होनी चाहिए कि उसका दायित्व क्या है, और उसकी ओर से कमीशन या चूक का कौन सा कार्य एक आपराधिक अपराध होगा। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को हाइड्रोजनीकृत तेलों को आइटम 15 और 16 में शामिल करके अपनी मंशा स्पष्ट और स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी चाहिए थी, जो 'वनस्पति' को संदर्भित करते हैं। यदि ऐसा किया जाता, तो इस मामले में उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की दुर्दशा से आसानी से बचा जा सकता था, और इससे समुदाय को लाभ हो सकता था। हम आशा करते हैं कि अनुसूची में इस कमी को जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा।

यह खेदजनक है लेकिन हमारे पास बरी होने की पुष्टि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, हालांकि पूरी तरह से अलग कारणों से। इसलिए, उच्च न्यायालय के इस तर्क को दरकिनार करते हुए कि खंड 3 का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है, जब तक कि 1966 के आदेश के खंड 4 का भी उल्लंघन नहीं होता है, हम अपीलों को खारिज करते हैं और बरी करने के आदेशों की पुष्टि करते हैं कि यह दर्शाने वाले सबूतों की पूरी कमी है कि प्रतिवादी 'वनस्पति' के व्यापारी हैं और उन्होंने अपनी दुकानों में 'वनस्पति' को बिक्री के लिए रखा था।

एस. आर.

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सपना राजपुरोहित द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।